



दैनिक समाचार पत्र

भारतार्थ खबर

खबर नहीं, उसका अर्थ

देश | समाज | राजनीति | अर्थव्यवस्था | शिक्षा | संस्कृति | दुनिया



तकनीक और नवाचार से जन-जन तक अवसर पहुँचाने पर पीएम मोदी का जोर



भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com
संवाददाता अशोक कुमार सिंह
नई दिल्ली, 13 अक्टूबर 2026 ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तकनीक, डेटा, ज्ञान और नवाचार को व्यापक जनसशक्तीकरण का माध्यम बनाने पर जोर देते हुए कहा कि आधुनिक

युग में इन संसाधनों की वास्तविक उपयोगिता इस बात से तय होती है कि इनके जरिए कितने लोगों के लिए विकास और प्रगति के नए अवसर तैयार किए जाते हैं। मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित जनसशक्तीकरण का माध्यम बनाने का ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में उन्होंने तकनीकी क्षमता का लाभ

समाज के अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री के संदेश का प्रमुख भाव 'पावर टू एम्पावर' यानी दूसरों को शक्त बनाने की शक्ति रहा। इसका आशय है कि तकनीकी विकास का लाभ केवल चुनिंदा लोगों या संस्थानों तक सीमित न रहे, बल्कि आम नागरिकों, युवाओं, छोटे कारोबारियों और नए उद्यमियों को भी आगे बढ़ने के अवसर मिलें। डिजिटल भारत से रोजगार और उद्यमिता को मिल सकती है गति भारत की विकास यात्रा में डिजिटल बुनियादी ढाँचे, स्टार्टअप और नवाचार की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है। डिजिटल सेवाओं के विस्तार से छोटे व्यवसायों को ग्राहकों तक पहुँचने, युवाओं को नए कौशल विकसित करने और उद्यमियों को अपने कारोबार का विस्तार करने में सहायता मिल सकती है। डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन सेवाओं और तकनीक आधारित कारोबारी समाधानों ने आर्थिक गतिविधियों के लिए नए रास्ते खोले हैं। इन सुविधाओं का प्रभावी उपयोग रोजगार सृजन, व्यावसायिक दक्षता और बाजार तक

पहुँच बढ़ाने में सहायक हो सकता है। हालाँकि, इसका व्यापक लाभ सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल साक्षरता, इंटरनेट की उपलब्धता और तकनीकी संसाधनों तक समान पहुँच भी आवश्यक है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितताओं के बीच देशों के बीच विश्वास, सहयोग और साझा प्रगति की आवश्यकता बढ़ गई है। आर्थिक एवं तकनीकी विकास का उद्देश्य केवल प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ना नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्थाओं को मजबूत करना भी होना चाहिए जिनसे व्यापक स्तर पर लोगों को लाभ मिल सके। इस संदर्भ में सुधारों और वैश्विक साझेदारियों का महत्व बढ़ जाता है। विभिन्न देशों के बीच तकनीकी ज्ञान, अनुभव और संसाधनों का आदान-प्रदान नए निवेश, नवाचार तथा कारोबारी अवसरों को प्रोत्साहित कर सकता है। साथ ही, सहयोग की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करेगी कि उससे मिलने वाले लाभ कितने व्यापक और समावेशी होते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ सकता है प्रभाव? तकनीक और नवाचार को विकास का प्रमुख आधार

बनाने की दिशा में भारत के स्टार्टअप, डिजिटल भुगतान, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और छोटे कारोबारों के लिए नई संभावनाएँ बन सकती हैं। तकनीकी समाधान बाजार तक पहुँच आसान करने, सेवाओं की लागत घटाने और कामकाज की दक्षता बढ़ाने में उपयोगी साबित हो सकते हैं। इसके बावजूद, तकनीकी प्रगति अपने आप में समान अवसरों की गारंटी नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में डिजिटल सुविधाओं की उपलब्धता, युवाओं का कौशल विकास, साइबर सुरक्षा तथा तकनीकी सेवाओं की सामर्थ्य जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण बने हुए हैं। इन चुनौतियों पर प्रभावी काम होने से ही तकनीकी विकास का लाभ समाज के व्यापक वर्ग तक पहुँच सकेगा। प्रधानमंत्री का संदेश इस विचार को सामने रखता है कि विकास की सफलता केवल तकनीकी संसाधनों या आर्थिक क्षमता से नहीं मापी जानी चाहिए। उसका वास्तविक महत्व इस बात में है कि वह आम लोगों के जीवन में कितने सकारात्मक बदलाव लाता है और कितने लोगों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है।

2,000 से अधिक के चुनिंदा UPI भुगतानों पर शुल्क टला , दिवाली के बाद लागू होगी व्यवस्था

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com
संवाददाता अशोक कुमार सिंह
नई दिल्ली, 13 अक्टूबर 2026 ।

डिजिटल भुगतान से जुड़े कारोबारियों को फिलहाल राहत मिली है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने 2,000 से अधिक के चुनिंदा यूपीआई मर्चेंट लेनदेन पर प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने की तारीख आगे बढ़ा दी है। यह व्यवस्था पहले 15 अक्टूबर 2026 से लागू होनी थी। अब इसे दिवाली के तुरंत बाद लागू करने का निर्णय लिया गया है। नई तारीख अलग से घोषित की जाएगी। चुनिंदा कारोबारी भुगतानों पर 0.4 प्रतिशत शुल्क प्रस्तावित व्यवस्था के तहत पात्र व्यक्ति-से-व्यापारी (P2M) यूपीआई भुगतानों में 2,000 से अधिक की राशि पर 0.4 प्रतिशत तक डक्ट निर्धारित किया गया है। 75,000 या उससे अधिक के पात्र लेनदेन पर इसकी अधिकतम सीमा 300 प्रति लेनदेन रखी गई है। यह शुल्क भुगतान स्वीकार करने वाले पात्र कारोबारियों से संबंधित है, इसे प्रत्येक

यूपीआई उपयोगकर्ता पर सीधे लगाया जाने वाला शुल्क नहीं समझना चाहिए। आम ग्राहकों और छोटे कारोबारियों पर क्या असर होगा? व्यक्ति से व्यक्ति के बीच यूपीआई के माध्यम से पैसे भेजने और प्राप्त करने की व्यवस्था निःशुल्क बनी रहेगी। प्रस्तावित ढांचे



के अनुसार, 2,000 तक के पात्र मर्चेंट भुगतानों पर MDR नहीं लगेगा। वहीं, निर्धारित शर्तों के अंतर्गत आने वाले छोटे कारोबारियों को भी छूट जारी रहने की बात कही गई है। इसलिए नए शुल्क का प्रभाव सभी यूपीआई भुगतानों पर समान रूप से नहीं पड़ेगा। इसका दायरा लेनदेन के प्रकार, राशि और संबंधित कारोबारी की श्रेणी पर निर्भर करेगा। ग्राहकों के

लिए यह समझना भी जरूरी है कि MDR का भुगतान कारोबारी की जिम्मेदारी है और इसे ग्राहकों से वसूलने की अनुमति संबंधी निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। दिवाली के बाद क्यों लागू होगी व्यवस्था? त्योहारी मौसम में बाजारों में खरीदारी और डिजिटल भुगतान की गतिविधियाँ बढ़ जाती हैं। ऐसे समय में नई शुल्क व्यवस्था लागू करने से कारोबारियों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को अतिरिक्त बदलाव करने पड़ सकते हैं। तारीख आगे बढ़ाने से संबंधित पक्षों को तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा और त्योहार के दौरान भुगतान व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने में मदद मिल सकती है। नई तारीख पर रहेगी नजर छच्छ की ओर से नई प्रभावी तारीख और परिचालन संबंधी निर्देशों की घोषणा का इंतजार है। कारोबारियों को अपने बैंक या भुगतान सेवा प्रदाता से यह पता कर लेना चाहिए कि प्रस्तावित व्यवस्था उनके लेनदेन पर किस प्रकार लागू होगी। यूपीआई देश में खुदरा डिजिटल भुगतान का प्रमुख माध्यम बन चुका है।

लद्दाख के नए नामों पर भारत-चीन में तकरार, बीजिंग ने जताया कड़ा विरोध

भारतार्थ खबरBhaarataarth.com
नई दिल्ली, 13 अक्टूबर 2026 । लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों के नामों को लेकर भारत और चीन के बीच कूटनीतिक विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है। भारत की ओर से सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए नए मानक नाम जारी किए जाने और उन्हें आधिकारिक दस्तावेजों में शामिल किए जाने पर चीन ने कड़ी आपत्ति जताई है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने 13 अक्टूबर को कहा कि चीन लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता नहीं देता और भारत की ओर से जारी किए गए नए नामों का विरोध करता है। दूसरी ओर, भारत की नीति रही है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं तथा देश की संप्रभुता से जुड़े फैसले लेने का अधिकार भारत के पास है। 28 स्थानों के नामों को लेकर विवाद उपलब्ध विवरण के अनुसार, भारत सरकार ने लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित 28 स्थानों के मानक नाम निर्धारित करने की पहल की है। इस कदम को सीमावर्ती क्षेत्रों के आधिकारिक अभिलेखों और भौगोलिक पहचान को व्यवस्थित करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। हालाँकि, इन 28 स्थानों की सूची और संबंधित सरकारी अधिसूचना की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है। सीमा से जुड़े मामलों में स्थानों के नाम केवल भौगोलिक पहचान तक सीमित नहीं रहते, बल्कि उनका कूटनीतिक और प्रशासनिक महत्व भी होता है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद लंबे समय से अनसुलझा है। ऐसे में आधिकारिक नक्शों और दस्तावेजों में किए गए बदलावों पर दोनों देशों की प्रतिक्रियाएँ उनके परस्पर विरोधी दावों को सामने लाती हैं। चीन ने क्या कहा? चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने भारत की कार्रवाई का विरोध करते हुए कथित तौर पर कहा कि चीन तथाकथित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को मान्यता नहीं देता।



भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com
कीव/मॉस्को, 13 अक्टूबर 2026 ।
रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में ऊर्जा प्रतिष्ठाओं को निशाना बनाए जाने की खबरों ने एक बार फिर नागरिक सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर चिंता बढ़ा दी है। बिजली उत्पादन केंद्रों और ऊर्जा आपूर्ति से जुड़े बुनियादी ढाँचे पर हमलों के बीच प्रस्तावित युद्धविराम की प्रभावशीलता पर भी सवाल उठ रहे हैं। संघर्ष का असर दोनों देशों

रहें। रूस की ओर से इस कथित समझौते की स्पष्ट पुष्टि सामने नहीं आने से युद्धविराम की स्थिति को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इस घटनाक्रम ने यह सवाल खड़ा किया है कि क्या दोनों पक्ष वास्तव में ऊर्जा प्रतिष्ठाओं को हमलों से अलग रखने के लिए सहमत हैं और ऐसी किसी व्यवस्था को जमीन पर लागू करने की प्रभावी निगरानी कैसे होगी। युद्धविराम की घोषणा तभी सार्थक हो सकती है, जब संबंधित पक्ष उसकी शर्तों का पालन करें और उल्लंघन की स्थिति में जवाबदेही सुनिश्चित हो। ऊर्जा ठिकानों पर हमले रोकने की पहल यूक्रेन ने संकेत दिया है कि यदि रूस उसके ऊर्जा ढाँचे पर हमले रोकता है, तो वह भी रूसी तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाने की कार्रवाई रोकने के लिए तैयार है। यह संकेत संभावित आपसी सहमति की गुंजाइश दिखाता है, लेकिन इसे स्थायी व्यवस्था में बदलने के लिए स्पष्ट शर्तें, दोनों पक्षों की प्रतिबद्धता और

प्रभावी निगरानी आवश्यक होगी। ऊर्जा प्रतिष्ठाएं किसी भी देश की अर्थव्यवस्था और नागरिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इन पर हमलों से बिजली उत्पादन, औद्योगिक गतिविधियों, परिवहन और आवश्यक सेवाओं पर असर पड़ सकता है। इसलिए ऊर्जा ढाँचे की सुरक्षा को लेकर किसी भी समझौते का महत्व केवल सैन्य टकराव कम करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध आम लोगों के जीवन से भी है। यूरोपीय संघ ने बढ़ाया दबाव युद्ध के बीच यूरोपीय संघ ने रूस के सैन्य-औद्योगिक तंत्र से जुड़े लोगों और संस्थाओं पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। यूरोपीय देशों की चिंता है कि लगातार सैन्य कार्रवाई से संघर्ष लंबा खिंच सकता है और क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ सकती है। हालाँकि, प्रतिबंधों का वास्तविक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि वे रूस की सैन्य क्षमताओं, आर्थिक गतिविधियों और युद्ध संबंधी फैसलों को किस हद तक प्रभावित कर पाते हैं। इसके साथ

ही कूटनीतिक प्रयासों को जारी रखना भी जरूरी है, ताकि तनाव कम करने और बातचीत की संभावनाओं को मजबूत किया जा सके। सर्दियों से पहले नागरिकों की चिंता सर्दियों के नजदीक आने के साथ ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। बिजली संयंत्रों, वितरण नेटवर्क और अन्य ऊर्जा प्रतिष्ठाओं को नुकसान पहुँचने से नागरिकों को बिजली, पानी, हीटिंग और स्वास्थ्य सेवाओं जैसी बुनियादी सुविधाओं में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। विशेष रूप से बुजुर्गों, बच्चों, बीमार लोगों और कमजोर परिस्थितियों में रह रहे परिवारों पर ऐसी स्थिति का अधिक असर पड़ सकता है। ऊर्जा ढाँचे को नुकसान पहुँचने से मरम्मत और आपूर्ति बहाल करने में भी समय लग सकता है। इसलिए नागरिकों की सुरक्षा, आवश्यक सेवाओं की निरंतरता और मानवीय सहायता को प्राथमिकता देना आवश्यक है। स्थायी शांति के लिए संवाद जरूरी रूस-यूक्रेन युद्ध

का मौजूदा घटनाक्रम बताता है कि केवल युद्धविराम की घोषणा से संघर्ष समाप्त होने की गारंटी नहीं मिलती। इसके लिए दोनों पक्षों के बीच स्पष्ट सहमति, प्रतिबद्धताओं का पालन और विवादों के समाधान के लिए निरंतर संवाद जरूरी है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। कूटनीतिक प्रयासों के माध्यम से ऊर्जा प्रतिष्ठाओं और नागरिक सुरक्षाओं को निशाना बनाए जाने से रोकने, मानवीय संकट कम करने तथा बातचीत के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए। अंततः, युद्ध का स्थायी समाधान सैन्य कार्रवाई के बजाय विस्वसनीय संवाद, आपसी सहमति और सुरक्षा संबंधी चिंताओं के व्यावहारिक समाधान से ही संभव हो सकता है। ऊर्जा ठिकानों पर हमले रोकने की किसी भी पहल की सफलता इस बात से तय होगी कि वह कागजी घोषणा से आगे बढ़कर जमीन पर कितनी प्रभावी साबित होती है।

रुपये को मिली राहत, लेकिन महँगाई ने बढ़ाई चिंता RBI के सामने दोहरी चुनौती

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com
संवाददाता अशोक कुमार सिंह
नई दिल्ली, 13 अक्टूबर 2026 ।
अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में सुधार के संकेतों के बीच भारत की अर्थव्यवस्था के सामने महँगाई पर नियंत्रण बनाए रखने की चुनौती बनी हुई है। एक ओर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) विदेशी मुद्रा बाजार में दबाव कम करने के लिए नियामकीय उपाय कर रहा है, वहीं दूसरी ओर खुदरा और खाद्य महँगाई में बढ़ोतरी से आम परिवारों के बजट पर दबाव बढ़ने की आशंका है। ऐसे में रुपये की स्थिरता और वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण आर्थिक नीति के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे बने हुए हैं। 13 अक्टूबर 2026 को उपलब्ध बाजार रिपोर्ट के अनुसार, डॉलर के मुकाबले रुपये में सुधार दर्ज किया गया। हालाँकि, मुद्रा बाजार में किसी एक दिन या सीमित अवधि के सुधार को स्थायी मजबूती का संकेत मानना जल्दबाजी होगी। रुपये की दिशा पर कच्चे तेल की कीमतों, विदेशी निवेश के प्रवाह, डॉलर की वैश्विक स्थिति और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक परिस्थितियों का भी प्रभाव पड़ता है। सितंबर में खुदरा महँगाई बढ़कर 5.54 प्रतिशत सितंबर 2026 के उपलब्ध

आँकड़ों के अनुसार, भारत की खुदरा महँगाई दर अगस्त के 4.83 प्रतिशत से बढ़कर 5.54 प्रतिशत हो गई। इसी अवधि में खाद्य महँगाई दर भी 5.97 प्रतिशत से बढ़कर 7.74 प्रतिशत पर पहुँच गई। खाद्य वस्तुओं

मजबूती केवल नियामकीय फैसलों पर निर्भर नहीं करती। भारत की कच्चे तेल सहित ऊर्जा आयात पर निभरता, व्यापार घाटा, विदेशी निवेशकों की गतिविधियाँ और वैश्विक वित्तीय परिस्थितियाँ भी मुद्रा विनिमय दर को प्रभावित करती हैं। यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो भारत का आयात बिल बढ़ सकता है। इससे डॉलर की माँग पर दबाव पड़ने की आशंका रहती है। इसके विपरीत, विदेशी पूँजी का मजबूत प्रवाह और राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेन्स्की ने आरोप लगाया कि घोषणा के बाद भी यूक्रेनी ऊर्जा ठिकानों पर हमले जारी

लागातार वृद्धि होने पर घरेलू बचत घटने और गैर-जरूरी खर्चों में कटौती की स्थिति बन सकती है। व्याज दरों को लेकर RBI के आगामी फैसले भी महँगाई के रुझान, आर्थिक विकास और अन्य व्यापक आर्थिक संकेतकों के आकलन पर निर्भर करेंगे। महँगाई लंबे समय तक ऊँची बनी रहती है, तो मौद्रिक नीति के विकल्पों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। आगे की राह रुक मुद्रा स्थिरता के साथ महँगाई पर नियंत्रण जरूरी आने वाले समय में रुपये की चाल, खाद्य वस्तुओं की कीमतें, कच्चे तेल का अंतरराष्ट्रीय बाजार और विदेशी निवेश अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने वाले प्रमुख संकेतक रहेंगे। तत्पक्ष सामने चुनौती विदेशी मुद्रा बाजार में अनावश्यक उतार-चढ़ाव को सीमित करने के साथ महँगाई को नियंत्रित रखने की है। रुपये में सुधार से बाजार को कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन इसका लाभ तभी व्यापक होगा जब मुद्रा बाजार में स्थिरता के साथ घरेलू कीमतों पर भी नियंत्रण कायम हो। सितंबर में खुदरा और खाद्य महँगाई में दर्ज वृद्धि संकेत देती है कि आर्थिक दबाव को कम करने के लिए सतत निगरानी और प्रभावी नीतिगत कदमों की आवश्यकता बनी हुई है।

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com
नई दिल्ली, 13 अक्टूबर 2026 ।
चुनाव आयोग की निष्पक्षता और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर जारी



राजनीतिक विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। मंगलवार को केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह (ललन सिंह) के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोयल ने कांग्रेस के पुराने फैसलों और चुनाव आयोग से जुड़े अधिकारियों को चुनवा आयोग के कामकाज को लेकर अलग-अलग विचार सामने आए हैं। एसआईआर और चुनाव आयोग पर कांग्रेस के रुख को लेकर सवाल पीयूष गोयल ने अपने संबोधन में कांग्रेस नेता शशि थरूर, रमेश चैन्निथला और अनिरुध्न चौधरी के बयानों का उल्लेख किया। उनके अनुसार, इन नेताओं ने अलग-अलग चैनलिथला और अनिरुध्न चौधरी के बयानों का उल्लेख किया। उनके अनुसार, इन नेताओं ने अलग-अलग चैनलिथला और अनिरुध्न चौधरी के बयानों का उल्लेख किया। उनके अनुसार, इन नेताओं ने अलग-अलग चैनलिथला और अनिरुध्न चौधरी के बयानों का उल्लेख किया।

अधिकारियों को दिए गए राजनीतिक पदों और जिम्मेदारियों पर पर्याप्त स्पष्टीकरण नहीं देती। उन्होंने राहुल गांधी को कांग्रेस के लिए बड़ा राजनीतिक जोखिम बताते हुए कहा कि पार्टी के भीतर से भी एसआईआर और चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर अलग-अलग विचार सामने आए हैं। एसआईआर और चुनाव आयोग पर कांग्रेस के रुख को लेकर सवाल पीयूष गोयल ने अपने संबोधन में कांग्रेस नेता शशि थरूर, रमेश चैन्निथला और अनिरुध्न चौधरी के बयानों का उल्लेख किया। उनके अनुसार, इन नेताओं ने अलग-अलग चैनलिथला और अनिरुध्न चौधरी के बयानों का उल्लेख किया। उनके अनुसार, इन नेताओं ने अलग-अलग चैनलिथला और अनिरुध्न चौधरी के बयानों का उल्लेख किया।

आयुक्तों की नियुक्तियों का उठाया मुद्दा केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस के शासनकाल में चुनाव आयोग से जुड़े कुछ पूर्व अधिकारियों को बाद में मिले राजनीतिक या सरकारी पदों का उल्लेख करते हुए संस्थागत निष्पक्षता पर सवाल उठाए। गोयल ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन का उदाहरण देते हुए कहा कि वर्ष 1999 में उन्हें भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी के मुकाबले कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने का अवसर दिया गया था। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इस तरह की राजनीतिक भूमिका चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को लेकर संदेह पैदा नहीं करती। उन्होंने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एम.एस. गिल का भी उल्लेख किया। गिल वर्ष 1996 से 2001 तक मुख्य चुनाव आयुक्त रहे थे। गोयल के अनुसार, बाद में गिल कांग्रेस में शामिल हुए, राज्यसभा सदस्य बने और केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी शामिल किए गए। उन्होंने इन घटनाओं को चुनाव आयोग से जुड़े अधिकारियों की सेवानिवृत्ति के बाद राजनीतिक नियुक्तियों के संदर्भ में उठाया। गोयल ने केरल के पूर्व मुख्य निर्वाचन अधिकारी टीकाशम मीणा और रतन यू, केलकर का उल्लेख करते हुए भी नियुक्तियों से संबंधित सवाल उठाए।

सम्पादकीय

महा कंजूस लाला

घनश्यामदास की कहानी

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com

एक गाँव में लाला घनश्यामदास नाम का एक आदमी रहता था।

वह इतना बड़ा कंजूस था कि लोग उसके नाम से कम और उसकी कंजूसी के किस्सों से ज्यादा उसे जानते थे। लाला के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। घर में सोने—चाँदी के गहने, तिजोरी में नोटों की गड़्डियाँ और जमीन—जायदाद भी खूब थी। लेकिन मजाल है कि वह अपनी जेब से एक रुपया भी खर्च कर दे! कंजूसी की हद एक दिन लाला बाजार जा रहा था। रास्ते में उसे प्यास लगी। उसने एक दुकानदार से पानी माँगा। दुकानदार बोला, “लालाजी, पानी का गिलास दो रुपये का है।” लाला तुरंत पीछे हट गया और बोला, “दो रुपये का पानी! वह प्यासा ही आगे चल पड़ा। थोड़ी दूर पर एक मंदिर था। वहाँ नल से पानी बह रहा था। लाला ने खूब पानी पिया और जाते—जाते नल भी



बंद कर दिया। फिर खुद से बोला, “वाह घनश्याम! आज दो रुपये बच गए!” लेकिन उसे क्या पता था कि आगे उसकी कंजूसी का सबसे बड़ा इतिहास इंतजार कर रहा है।जब घर में लगी आग एक रात लाला के घर में अचानक आग लग गई। नौकर चिल्लाया, “मालिक! चल्दी बाहर चलिए!” लाला घबराकर उठा, लेकिन बाहर भागने के बजाय तिजोरी की तरफ दौड़ा। नौकर चिल्लाया, “मालिक, जान बचाइए!” लाला बोला, “पागल हो गया है क्या? तिजोरी में मेरी जिंदगी भर की कमाई है!” वह नोटों की गड़्डियाँ समेटने लगा। तभी उसकी धोती एक कील में फँस गई। नौकर ने उसे खींचकर बाहर निकाला। किसी तरह दोनों जान बचाकर घर से बाहर आ गए। लाला ने देखा कि उसका एक जूता आग में जल गया था। वह सिर पकड़कर बैठ गया और रोने लगा। नौकर ने पूछा, “मालिक, आप तो बच गए! लाला छाती पीटकर बोला, “अरे मूर्ख! वह जूता नया था! पूरे तीन सौ रुपये का।” नौकर ने माथा पकड़ लिया। कंजूस का आखिरी दौंव अगली सुबह लाला ने सोचा कि अब वह घर की मरम्मत पर एक पैसा भी खर्च नहीं करेगा। वह गाँव के मिस्त्री के पास गया और बोला, “भाई, मेरे घर की छत ठीक कर दो। पैसे बाद में दूँगा।” मिस्त्री बोला, “लालाजी, पहले पैसे दीजिए।” लाला ने कहा, “अच्छा, पैसे नहीं दूँगा। लेकिन तुम्हें आशीर्वाद जरूर दूँगा।” मिस्त्री हँसकर बोला, “लालाजी, आशीर्वाद से मेरा चूल्हा नहीं जलेगा!” लाला नाराज होकर लौट आया। कुछ दिन बाद बारिश हुई। छत से पानी टपकने लगा। लाला ने पानी रोकने के लिए घर में बाल्टियाँ रख दीं। फिर बाल्टियाँ भर गई तो उसने बर्तन रख दिए। आखिरकार उसका बिस्तर भी भीग गया। वह रात भर बैठा रहा और सुबह चिल्लाया “हाय रे किस्मत! अगर मैं समय पर छत ठीक करा देता, तो आज चौन से सो रहा होता।” नौकर ने मुस्कुराकर कहा, “मालिक, आपने पैसे तो खूब बचाए, लेकिन अपनी नींद, आराम और सुकून सब गँवा दिया।” लाला पहली बार चुप हो गया। कहानी की सीख पैसा बचाना अच्छी आदत है, लेकिन जरूरत के समय पैसा खर्च न करना मूर्खता है। धन इंसान के सुख और सुरक्षा के लिए है, इंसान धन का गुलाम बनने के लिए नहीं। और हाँ, गाँव में आज भी जब कोई जरूरत से ज्यादा कंजूसी करता है, तो लोग हँसकर कहते हैं “संमलकर भाई! कहीं तुम भी गाँव के लाला घनश्यामदास न बन जाना।” लेखक: अशोक कुमार सिंह



भारतार्थ खबर

Bhaarataarth.com

दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा है। मतदाता सूची से कथित तौर पर बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने के आरोपों के बीच विपक्षी दलों और विभिन्न प्रदर्शनकारी समूहों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग उठाई है। मंगलवार, 13 अक्टूबर को जंतर—मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने की जानकारी सामने आई। इस घटनाक्रम ने चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और मतदाताओं के अधिकारों को लेकर जारी बहस को और तेज कर दिया है। विवाद का प्रमुख केंद्र यह है कि

मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान किसी भी पात्र नागरिक का नाम गलत तरीके से सूची से बाहर न हो। विपक्षी दलों ने प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं, जबकि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के साथ प्रत्येक पात्र नागरिक के मतदान के अधिकार की रक्षा भी की जाए। मतदाता सूची पुनरीक्षण पर उठे सवाल मतदाता सूची का पुनरीक्षण चुनावी व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका उद्देश्य अपात्र प्रविष्टियों को हटाना, गलतियों को सुधारना और पात्र नागरिकों के नाम सूची में सुनिश्चित करना है। हालांकि, इस प्रक्रिया की विव्सनीयता तभी कायम रह सकती है, जब नियमों का पालन पारदर्शी ढंग से हो और किसी भी

वैश्विक अर्थव्यवस्था की अग्निपरीक्षा:एआई निवेश, बढ़ता कर्ज और युद्ध के

भारतार्थ खबर

Bhaarataarth.com

वैश्विक अर्थव्यवस्था आज ऐसे दौर से गुजर रही है, जहां तकनीकी क्रांति से पैदा हुई उम्मीदें, सरकारों पर बढ़ता कर्ज और भू—राजनीतिक संघर्ष एक साथ आर्थिक स्थिरता की परीक्षा ले रहे हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) में बड़े पैमाने पर निवेश ने उत्पादकता और आर्थिक विकास की नई संभावनाएं खोली हैं, लेकिन इस क्षेत्र में अपेक्षित लाभ नहीं मिलने की आशंका भी बढ़ रही है। दूसरी ओर, सरकारी कर्ज की लागत और मध्य पूर्व में जारी संघर्ष ने ऊर्जा बाजारों तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ऐसे समय में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से संबंधित आर्थिक जोखिमों पर चर्चा केवल बाजारों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसका आकलन आम नागरिकों, रोजगार और विकासशील देशों के हितों के संदर्भ में भी होना चाहिए। तकनीकी क्रांति और निवेश की वास्तविकता पिछले कुछ वर्षों में एआई वैश्विक अर्थव्यवस्था के सबसे चर्चित निवेश क्षेत्रों में शामिल हुआ है। बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियां डेटा सेंटर, कंप्यूटिंग क्षमता, अत्याधुनिक चिप और नई डिजिटल सेवाओं के विकास पर भारी खर्च कर रही हैं। इससे

तकनीकी नवाचार को गति मिली है और उद्योगों के काम करने के तरीकों में बदलाव की संभावनाएं बढ़ी हैं। लेकिन हर नई तकनीक के साथ निवेश और अपेक्षाओं के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक होता है। यदि कंपनियां भविष्य में भारी मुनाफे की उम्मीद में अत्यधिक निवेश करती हैं



और वास्तविक आय उस स्तर तक नहीं पहुंचती, तो बाजार में सुधार की स्थिति बन सकती है। ऐसी परिस्थिति में कंपनियों के मूल्यांकन में गिरावट, नई परियोजनाओं में कटौती और निवेशकों के विश्वास में कमी आ सकती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि एआई का विकास आर्थिक संकट का कारण बनेगा। वास्तविक प्रश्न यह है कि तकनीकी निवेश से कितनी उत्पादकता

संपादकीय

का सामना न करना पड़े। दिल्ली में

पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान लगभग 33 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाने और करीब 20 लाख मामलों के निपटारे संबंधी आंकड़े चर्चा में हैं। इन आंकड़ों का आकलन करते समय यह अंतर समझना जरूरी है कि नोटिस जारी होना अपने आप में मतदाता का नाम हटाए जाने का प्रमाण नहीं है। प्रत्येक मामले में नोटिस का कारण, संबंधित दस्तावेज, सुनवाई और अंतिम निर्णय की स्थिति अलग—अलग हो सकती है। इन आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि तथा आधिकारिक विवरण के आधार पर ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित होगा। पात्र मतदाता अपना नाम कैसे जांचें? चुनाव आयोग की निर्धारित प्रक्रिया के तहत नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम और संबंधित विवरण जांच सकते हैं। यदि किसी पात्र नागरिक का नाम सूची में नहीं मिलता, तो लागू नियमों के अनुसार फॉर्म—6 के माध्यम से नाम शामिल कराते लिए आवेदन किया जा सकता है। आवेदन करने से पहले संबंधित निर्वाचन अधिकारी से मौजूदा प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी लेना उपयोगी होगा। चुनाव प्रशासन के लिए जरूरी है कि नाम जोड़ने, हटाने और संशोधित करने से जुड़ी प्रक्रियाओं की जानकारी सरल

भाषा में उपलब्ध कराई जाए। जिन नागरिकों को नोटिस जारी किए गए हैं, उन्हें उसका कारण समझने, आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने और निर्धारित समय के भीतर अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। मतदाता सूची की शुद्धता और मताधिकार की सुरक्षा एक—दूसरे के विरोधी उद्देश्य नहीं हैं। सही प्रक्रिया के माध्यम से दोनों लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है। इसके लिए शिकायतों का समयबद्ध निपटारा और निर्णयों की स्पष्ट जानकारी महत्वपूर्ण है। इस्तीफे की मांग से बढ़ा राजनीतिक टकराव मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी दलों ने अपना विरोध तेज किया है। कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी नेताओं ने पुनरीक्षण प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए पारदर्शिता की मांग की है। आम आदमी पार्टी की ओर से 15 अक्टूबर को दिल्ली में बड़े प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन अनशन की घोषणा के लिए जाने की जानकारी भी सामने आई है। दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के आरोपों को राजनीतिक अभियान का हिस्सा बताया है। इस तरह मतदाता सूची से जुड़ा प्रशासनिक विषय अब राजनीतिक दलों के बीच टकराव का मुद्दा बन गया है। हालांकि,

इस्तीफे की मांग करना राजनीतिक विरोध का हिस्सा है, लेकिन आरोपों की सत्यता का निर्धारण तथ्यों, दस्तावेजों और संबंधित प्रक्रियाओं के आधार पर ही किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, आरोपों को केवल राजनीतिक बयान मानकर खारिज करने के बजाय उन शिकायतों की जांच करना भी आवश्यक है, जिसमें किसी पात्र मतदाता के अधिकार का उल्लंघन हुआ हो। इसके लिए लोकतांत्रिक केवल मतदान के दिन की व्यवस्थाओं पर निर्भर नहीं करती। मतदाता सूची में पात्र नागरिकों का सही तरीके से पंजीकरण भी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की बुनियादी शर्त है। यदि किसी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में बना रहता है, तो यह प्रशासनिक समस्या है। उसी तरह, किसी पात्र नागरिक का नाम गलत तरीके से हट जाना भी गंभीर विषय है। इसलिए पुनरीक्षण के दौरान दोनों प्रकार की त्रुटियों को दूर करने के लिए स्पष्ट नियम, निष्पक्ष सुनवाई और प्रभावी शिकायत निवारण व्यवस्था जरूरी है। राजनीतिक दलों की भी जिम्मेदारी है कि वे अनियमितताओं के आरोपों के समर्थन में विशिष्ट मामलों और उपलब्ध प्रमाणों को उचित

मंच पर प्रस्तुत करें। इससे शिकायतों की जांच अधिक प्रभावी हो सकती है और राजनीतिक बहस तथ्यों पर केंद्रित रह सकती है। शांतिपूर्ण विरोध और प्रशासन की जिम्मेदारी लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध नागरिकों और राजनीतिक संगठनों को अपनी असेहमति व्यक्त करने का अवसर देता है। वहीं, पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि कानून—व्यवस्था बनाए रखते हुए विरोध के अधिकार का सम्मान किया जाए। हिरासत में लिए गए लोगों के मामले में लागू कानूनी प्रक्रिया का पालन और कार्रवाई के कारणों की स्पष्टता भी महत्वपूर्ण है। चुनाव आयोग की विव्सनीयता बनाए रखने के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और शिकायतों का निष्पक्ष निपटारा आवश्यक है। सरकार, चुनाव प्रशासन, राजनीतिक दलों और नागरिक संगठनों को इस मुद्दे पर संयमित तथा तथ्यपरक भूमिका निभानी चाहिए। दिल्ली में जारी विवाद का समाधान केवल राजनीतिक बयानबाजी या इस्तीफे की मांग तक सीमित नहीं होना चाहिए। प्राथमिकता यह सुनिश्चित करने की होनी चाहिए कि प्रत्येक पात्र नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सके, किसी भी त्रुटि को समय पर सुधारा जा सके और चुनावी प्रक्रिया पर जनता का भरोसा बना रहे।

वैश्विक अर्थव्यवस्था की अग्निपरीक्षा:एआई निवेश, बढ़ता कर्ज और युद्ध के साये में विकास

विकास, डिजिटल बुनियादी ढांचे और अनुसंधान में निवेश जरूरी है। भारत को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि तकनीकी बदलाव का लाभ केवल बड़ी कंपनियों तक सीमित न रहे। छोटे उद्योगों, युवाओं और श्रमिकों को नई तकनीकों के अनुरूप प्रशिक्षण देना आवश्यक है, ताकि उत्पादकता में वृद्धि के साथ रोजगार के अवसर भी विकसित हों। संपादकीय दृष्टिकोण: विकास के साथ जवाबदेही जरूरी है। स्थायी आर्थिक राहत के लिए युद्धविराम और संवाद के प्रयासों को मजबूत करना आवश्यक है। भारत के सामने चुनौतियां और अवसर भारत के लिए इन तीनों परिस्थितियों का महत्व विशेष है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से आयात खर्च और महंगाई पर दबाव पड़ सकता है। रुपये की विनिमय दर में बदलाव भी आयात लागत को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में ऊर्जा स्रोतों में विविधता, घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन और वित्तीय स्थिरता बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। दूसरी ओर, एआई भारत के लिए नए अवसर पैदा कर सकता है। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, का वित्तीय सेवाओं और विनिर्माण में इसका जिम्मेदार उपयोग उत्पादन क्षमता बढ़ाने तथा सेवाओं की पहुंच सुधारने मेंसहायक हो सकता है। इसके लिए कोशल

विकास, डिजिटल बुनियादी ढांचे और अनुसंधान में निवेश जरूरी है। भारत को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि तकनीकी बदलाव का लाभ केवल बड़ी कंपनियों तक सीमित न रहे। छोटे उद्योगों, युवाओं और श्रमिकों को नई तकनीकों के अनुरूप प्रशिक्षण देना आवश्यक है, ताकि उत्पादकता में वृद्धि के साथ रोजगार के अवसर भी विकसित हों। संपादकीय दृष्टिकोण: विकास के साथ जवाबदेही जरूरी है। स्थायी आर्थिक राहत के लिए युद्धविराम और संवाद के प्रयासों को मजबूत करना आवश्यक है। भारत के सामने चुनौतियां और अवसर भारत के लिए इन तीनों परिस्थितियों का महत्व विशेष है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से आयात खर्च और महंगाई पर दबाव पड़ सकता है। रुपये की विनिमय दर में बदलाव भी आयात लागत को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में ऊर्जा स्रोतों में विविधता, घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन और वित्तीय स्थिरता बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। दूसरी ओर, एआई भारत के लिए नए अवसर पैदा कर सकता है। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, का वित्तीय सेवाओं और विनिर्माण में इसका जिम्मेदार उपयोग उत्पादन क्षमता बढ़ाने तथा सेवाओं की पहुंच सुधारने मेंसहायक हो सकता है। इसके लिए कोशल

ऊर्जा युद्ध विराम की उम्मीद:रूस=यूक्रेन संघर्ष में घोषणा से ज्यादा जरूरी है भरोसा

भारतार्थ खबर

Bhaarataarth.com

रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को सीमित करने के लिए ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने की पहल ने एक बार फिर कूटनीति की संभावनाओं को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से 11 अक्टूबर को ऊर्जा युद्धविराम की घोषणा के बाद शांति की उम्मीद तो जगी है, लेकिन इसकी वास्तविक स्थिति, शर्तों और दोनों पक्षों की सहमति को लेकर अब भी स्पष्टता आवश्यक है। रूस ने 13 अक्टूबर को इस विषय पर संपर्क जारी रहने की बात कही है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या राजनीतिक घोषणा वास्तव में जमीन पर लागू होने वाली व्यवस्था में बदल पाएगी? युद्ध के लंबे दौर ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सैन्य कार्रवाई से किसी देश को नुकसान पहुंचाना और स्थायी शांति स्थापित करना दो अलग—अलग बातें हैं। ऊर्जा युद्धविराम की पहल इस अंतर को समझने का अवसर देती है। यदि दोनों देश बिजली संयंत्रों, ऊर्जा संपूर्ति नेटवर्क और ईंधन संबंधी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने से परहेज करते हैं, तो इससे आम नागरिकों को राहत मिल सकती है।

लेकिन इसके लिए घोषणाओं के साथ पारस्परिक प्रतिबद्धता, पारदर्शिता और प्रभावी निगरानी भी जरूरी होगी। ऊर्जा प्रतिष्ठान क्यों बने युद्ध का निर्णायक मोर्चा? आधुनिक युद्ध केवल सैनिकों और हथियारों तक सीमित नहीं रहता। बिजली, ईंधन, परिवहन और संचार व्यवस्था भी किसी देश की सामरिक क्षमता का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। ऊर्जा ढांचे पर हमले से औद्योगिक उत्पादन प्रभावित होता है, अस्पतालों और सार्वजनिक सेवाओं पर दबाव बढ़ता है तथा आम नागरिकों के दैनिक जीवन में गंभीर बाधाएं पैदा होती हैं। रूस और यूक्रेन के संघर्ष में ऊर्जा प्रतिष्ठानों की सुरक्षा इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिजली को आपूर्ति बाधित होने का प्रभाव व्यापक है। रूस और यूक्रेन के बीच अंतर का गुलाम बनने के लिए नहीं। और हाँ, गाँव में आज भी जब कोई जरूरत से ज्यादा कंजूसी करता है, तो लोग हँसकर कहते हैं “संमलकर भाई! कहीं तुम भी गाँव के लाला घनश्यामदास न बन जाना।” लेखक: अशोक कुमार सिंह

रूप में देखना उचित नहीं होगा। यह एक सीमित समझौता होगा, जिसकी उपयोगिता उसके वास्तविक पालन पर निर्भर करेगी। ट्रंप की



घोषणा और सहमति की चुनौती अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा ने ऊर्जा युद्धविराम को अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के केंद्र में ला दिया। लेकिन किसी समझौते की राजनीतिक घोषणा और उसके औपचारिक क्रियान्वयन के बीच अंतर रखना बड़ी चुनौती बन सकता है। ऊर्जा नेटवर्क की मरम्मत में समय और संसाधन दोनों लगते हैं, जबकि बार—बार होने वाले हमले पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को और कठिन बना देते हैं। इसलिए ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने की व्यवस्था मानवीय दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती है। हालांकि, इसे पूरे युद्ध के अंत के

रूस को भी यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे के विरुद्ध कार्रवाई रोकनी चाहिए। पारस्परिकता किसी भी युद्धविराम की विव्सनीयता का आधार है। एक पक्ष से संयम की अपेक्षा और दूसरे पक्ष के लिए अस्पष्ट छूट किसी भी समझौते को कमजोर कर सकती है। अमेरिका की कूटनीतिक भूमिका इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। उसे केवल सहमति की

घोषणा तक सीमित रहने के बजाय यह स्पष्ट करने में मदद करनी चाहिए कि युद्धविराम किन प्रतिष्ठानों पर लागू होगा, इसकी शुरुआत कब से मानी जाएगी और उल्लंघन की स्थिति पर क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। रूस का रुख और स्थायी शांति का प्रश्न क्रमेलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने 13 अक्टूबर को ऊर्जा युद्धविराम से संबंधित संपर्क जारी रहने की बात कही, लेकिन बातचीत में शामिल पक्षों और संभावित समझौते के विवरण को स्पष्ट नहीं किया। रूस की ओर से स्थायी शांति जोर दिए जाने का अर्थ है कि सीमित ऊर्जा युद्धविराम और व्यापक

राजनीतिक समाधान के बीच अंतर बना हुआ है। स्थायी शांति के लिए केवल हमलों को रोकना पर्याप्त नहीं होगा। इसके लिए सुरक्षा संबंधी चिंताओं, क्षेत्रीय विवादों, राजनीतिक मांगों और भविष्य में संघर्ष दोबारा शुरू होने की आशंकाओं पर भी विचार करना होगा। इन मुद्दों का समाधान कठिन और समय लेने वाला हो सकता है, लेकिन इन्हें नजरअंदाज करके हासिल किया गया अस्थायी विराम लंबे समय तक टिकने की गारंटी नहीं देता। इसी तरह, किसी एक रात में ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमलों की सूचना नहीं मिलने को स्थायी युद्धविराम का प्रमाण नहीं माना जा सकता। इसके लिए दोनों पक्षों के आधिकारिक वक्तव्यों, स्वतंत्र रूप से सत्यापित घटनाओं और लगातार किए गए पालन का आकलन आवश्यक है। वैश्विक अर्थव्यवस्था और भारत के हित रूस=यूक्रेन युद्ध का प्रभाव यूरोप तक सीमित नहीं रहा है। ऊर्जा आपूर्ति, परिवहन लागत, वैश्विक व्यापार और बाजारों में अनिश्चितता के कारण अनेक देशों की अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हुई हैं। ऊर्जा युद्धविराम प्रभावी होता है, तो इससे बाजारों को सकारात्मक संकेत मिल सकता है और आपूर्ति संबंधी

आशंकाओं में कुछ कमी आने की संभावना बन सकती है। भारत जैसे ऊर्जा आयात करने वाले देश के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्थिरता विशेष महत्व रखती है। कच्चे तेल की कीमतों में उतार—चढ़ाव का असर आयात बिल, महंगाई और आर्थिक नीतियों पर पड़ सकता है। फिर भी, ऊर्जा युद्धविराम की घोषणा के आधार पर पेट्रोल, डीजल या बिजली की कीमतों में तत्काल कमी की उम्मीद करना जल्दबाजी होगी। इन कीमतों पर वैश्विक मांग, आपूर्ति, परिवहन, विनिमय दर और विभिन्न देशों के नीतियों का भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए भारत के लिए सबसे व्यावहारिक दृष्टिकोण यह होगा कि वह अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम पर नजर रखते हुए ऊर्जा सुरक्षा, आपूर्ति के विविध स्रोतों और आर्थिक स्थिरता पर ध्यान बनाए रखे। संपादकीय दृष्टिकोण: शांति के लिए स्पष्ट नियम और जवाबदेही जरूरी ऊर्जा युद्धविराम की सफलता का मूल्यांकन तीन प्रमुख आधारों पर किया जाना चाहिए। पहला, दोनों पक्षों की स्पष्ट और औपचारिक सहमति हो। दूसरा, समझौते के पालन की निष्पक्ष निगरानी और उल्लंघनों की स्वतंत्र जांच की

व्यवस्था हो। तीसरा, किसी उल्लंघन की स्थिति में प्रतिक्रिया देने की प्रक्रिया पहले से निर्धारित हो, ताकि आरोप—प्रत्यारोप के कारण बातचीत पटरी से न उतरे। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भी यह समझना होगा कि युद्ध का सबसे बड़ा बोझ आम नागरिक उठाते हैं। कूटनीतिक प्रतिस्पर्धा और सामरिक हितों के बीच नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अस्पतालों, बिजली आपूर्ति और आवश्यक नागरिक सेवाओं को सुरक्षित रखने के प्रयास मानवीय जिम्मेदारी के साथ—साथ भविष्य में विश्वास बहाली का आधार भी बन सकते हैं। अमेरिका, यूरोपीय देशों और अन्य प्रभावशाली अंतरराष्ट्रीय पक्षों की भूमिका संवाद को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण हो सकती है। हालांकि, किसी भी बाहरी पहल की सफलता तभी संभव है, जब रूस और यूक्रेन स्वयं समझौते की शर्तों को स्वीकार करें और उनका ईमानदारी से पालन करें। दबाव से बातचीत शुरू कराई जा सकती है, लेकिन स्थायी शांति के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति और भरोसा आवश्यक है। निष्कर्ष: घोषणा नहीं, जमीन पर अमल तय करेगा

उपलब्ध विवरणों के आधार पर ऊर्जा युद्धविराम को लेकर कूटनीतिक संपर्क जारी रहने की बात सामने आई है, लेकिन इसकी विस्तृत शर्तों और प्रभावी क्रियान्वयन की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है। इसलिए इस पहल को न तो समय से पहले ऐतिहासिक सफलता घोषित करना उचित होगा और न ही इसकी संभावनाओं को खारिज करना। रूस और यूक्रेन के सामने अब अवसर है कि वे सीमित सहमति को मानवीय राहत और व्यापक बातचीत की दिशा में एक व्यावहारिक कदम बनाएं। यदि ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले वास्तव में रुकते हैं, तो इससे नागरिकों को राहत मिल सकती है और आपसी विश्वास बहाल करने का रास्ता खुल सकता है। लेकिन यदि घोषणा के बावजूद हमले जारी रहते हैं या शर्तों को लेकर विवाद बढ़ता है, तो शांति की उम्मीद फिर कमजोर पड़ सकती है। वास्तविक शांति का पैमाना बयानों की तीव्रता नहीं, बल्कि युद्ध की विभीषिका में आने वाली कमी है। ऊर्जा युद्धविराम तभी सार्थक होगा, जब वह कूटनीतिक मंचों से निकलकर जमीन पर दिखाई दे, नागरिकों की आवश्यक हो। निष्कर्ष: घोषणा नहीं, जमीन पर अमल तय करेगा

13 अक्टूबर 2026 तक

गर्भ संस्कार से संस्कारयुक्त पीढ़ी का निर्माण, वीरसागर जी महाराज ने बताया मातृ कल्याण का महत्व

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com बेंगलुरु, 13 अक्टूबर 2026। गर्भावस्था के दौरान मानसिक शांति, सकारात्मक विचारों, आध्यात्मिक जागरूकता और पारिवारिक सहयोग का महत्व रेखांकित करते हुए निर्यापक श्रमण श्री 108 वीरसागर जी महाराज ने ‘गर्भ संस्कार विशेष’ विषय पर प्रेरणादायी मार्गदर्शन दिया। इस प्रवचन में भारतीय संस्कृति में गर्भ संस्कार की परंपरा, भावी संतान के प्रति माता–पिता की जिम्मेदारी और परिवार में संस्कारयुक्त वातावरण विकसित करने के महत्व पर प्रकाश डाला गया। डिजिटल माध्यमों से श्रद्धालुओं, युवा दंपतियों और परिवारों तक पहुँचे इस संदेश में गर्भावस्था को केवल शाारीरिक परिवर्तन की अवस्था मानने के बजाय भावनात्मक, पारिवारिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझने की प्रेरणा दी गई। प्रवचन का प्रमुख संदेश रहा कि संतान के स्वागत की तैयारी के साथ–साथ माता के सम्मान, स्वास्थ्य, भावनात्मक सुरक्षा और परिवार के सहयोग को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। गर्भ संस्काररू



बल्कि गर्भावस्था के दौरान भी माता–पिता अपने व्यवहार और पारिवारिक मूल्यों के प्रति सजग रह सकते हैं। महाराज श्री के प्रवचन के संदर्भ में यह संदेश सामने आता है कि परिवार में प्रेम, सम्मान, धैर्य और मधुर संवाद का वातावरण बनाए

रखना महत्वपूर्ण है। गर्भवती महिला को भावनात्मक सहारा देना, उसकी आवश्यकताओं को समझना और धरेंलू परिस्थितियों में सहयोग करना प्रवचार जिम्मेदारियों में सहयोग करने का प्रत्येक सदस्य की साझा जिम्मेदारी है। मानसिक शांति और भावनात्मक सहयोग पर जोर आज की व्यस्त जीवनशैली में कार्यस्थल का दबाव, पारिवारिक जिम्मेदारियों और भविष्य की चिंताएँ अनेक लोगों के जीवन का हिस्सा हैं। ऐसी परिस्थितियों में गर्भवती महिला की भावनाओं को समझना और उसकी बात ध्यानपूर्वक सुनना विशेष महत्व रखता है। प्रवचन का व्यावहारिक संदेश है कि परिवार ऐसा वातावरण बनाए, जहाँ महिला अपनी चिंताओं और जरूरतों को बिना संकोच व्यक्त कर सके। सकारात्मक सोच का अर्थ कठिन भावनाओं को दबाना या हर परिस्थिति में प्रसन्न रहने का दबाव बनाना नहीं है। इसके बजाय, संवेदनशील व्यवहार, पर्याप्त विश्राम और जरूरत पड़ने पर उचित सहायता उपलब्ध कराना अधिक महत्वपूर्ण है। आहार, आध्यात्मिक साधना और संतुलित दिनचर्या गर्भ संस्कार की परंपरा में सात्त्विक आहार, सद्बिचार, ध्यान,

प्रार्थना, धार्मिक स्वाध्याय और आत्मचिंतन जैसे विषयों को महत्व दिया जाता है। अपनी आस्था और परिस्थितियों के अनुरूप इन गतिविधियों के लिए समय निकालना परिवार को संयम, अनुशासन और जीवन मूल्यों पर विचार करने का अवसर दे सकता है। गर्भावस्था में संतुलित पोषण भी आवश्यक है। महिला की व्यक्तिगत स्वास्थ्य स्थिति और पोषण संबंधी जरूरतों के अनुसार भोजन, पानी और आवश्यक पोषक तत्वों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके लिए योग्य चिकित्सक या पोषण विशेषज्ञ की सलाह महत्वपूर्ण है। इसी तरह ध्यान, मंत्र जाप और आध्यात्मिक अध्ययन व्यक्तिगत आस्था के अनुसार अपनाए जा सकते हैं, लेकिन इन्हें किसी विशेष स्वास्थ्य परिणाम की गारंटी या चिकित्सा के विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। परिवार की भूमिका से मजबूत होगा सहयोग का वातावरण गर्भावस्था के दौरान पति, माता–पिता, सास–ससुर और परिवार के अन्य सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। गर्भवती महिला को पर्याप्त विश्राम देना, धरेंलू कार्यों में सहयोग करना,

नियमित चिकित्सकीय जाँच के लिए सहायता उपलब्ध कराना और उसकी भावनाओं का सम्मान करना जिम्मेदार पारिवारिक व्यवहार के प्रमुख अंग हैं। परिवार में अनावश्यक तनाव और दबाव कम करने के साथ–साथ आपसी संवाद को बेहतर बनाना भी उपयोगी हो सकता है। यदि महिला लगातार चिंता, उदासी या अन्य भावनात्मक कठिनाइयों का सामना कर रही हो, तो उसकी बात को गंभीरता से सुनना और आवश्यकता के अनुसार स्वास्थ्य विशेषज्ञ की मदद लेना जरूरी है। आध्यात्मिक मूल्यों के साथ आधुनिक चिकित्सा भी जरूरी जैन दर्शन में अहिंसा, करुणा, संयम और आत्मानुशासन को विशेष महत्व दिया गया है। इन मूल्यों को पारिवारिक जीवन में अपनाने से सम्मानपूर्ण संबंधों, संवेदनशील व्यवहार और जिम्मेदार अभिभावकत्व को प्रोत्साहन मिल सकता है। हालाँकि, गर्भवती महिला और गर्भवश शिशु के स्वास्थ्य के लिए नियमित प्रसवपूर्व जाँच, योग्य चिकित्सक की सलाह और प्रमाण–आधारित चिकित्सा देखभाल आवश्यक हैं। आध्यात्मिक अभ्यास

व्यक्तिगत शांति और आत्मचिंतन का माध्यम हो सकते हैं, लेकिन वे चिकित्सकीय देखभाल का स्थान नहीं ले सकते।संस्कारयुक्त पीढ़ी के निर्माण का संदेशनिर्यापक श्रमण श्री 108 वीरसागर जी महाराज के गर्भ संस्कार विषयक मार्गदर्शन का व्यापक संदेश परिवारों को अपने आचरण, संबंधों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करना है। करुणा, संयम, अहिंसा, सदाचार और परस्पर सम्मान जैसे मूल्यों को दैनिक जीवन में अपनाकर माता–पिता आने वाली पीढ़ी के सामने सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं।गर्भ संस्कार की सार्थकता केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है। इसका व्यावहारिक स्वरूप ऐसा पारिवारिक वातावरण तैयार करना है, जिसमें गर्भवती महिला को सम्मान, सुरक्षा, सहयोग और आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएँ मिलें। संस्कारयुक्त भविष्य की नींव तभी मजबूत हो सकती है, जब आध्यात्मिक विचार संवेदनशील व्यवहार और जिम्मेदार जीवनशैली में दिखाई दें। समाचार प्रेषक विपिन कुमार जैन बेंगलुरु।

भक्ति और सेवा के संग मना गणेशोत्सव, जरूरतमंद बच्चों को बांगी शिक्षण सामग्री

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com बेंगलुरु, 13 अक्टूबर 2026। श्री विनायका गलेयारा बलेगा भैरवध्वर नगर की ओर से गणेश उत्सव भक्तिभाव, श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आयोजन में भगवान गणपति की आराधना के साथ सेवा और सामाजिक सरोकारों को भी विशेष महत्व दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महेंद्र मुणोत ने भगवान गणपति के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इस



अवसर पर उन्होंने जरूरतमंद बच्चों को शिक्षण सामग्री वितरित की तथा अन्नदान कार्यक्रम में सहभागी बनकर सेवा प्रदान की। उनके इस योगदान ने धार्मिक आयोजन के साथ सामाजिक जिम्मेदारी और जरूरतमंदों की सहायता के संदेश को भी प्रमुखता दी। आयोजकों ने महेंद्र मुणोत को सम्मानित किया। गणेश उत्सव के माध्यम से श्रद्धा, सेवा, सहयोग और सामाजिक सद्भाव की भावना को प्रोत्साहित किया गया। धार्मिक आस्था के साथ जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा और भोजन सेवा से जुड़ी गतिविधियों ने कार्यक्रम को सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बनाया। समाचार प्रेषक उपेन्द्र कुमार बेंगलुरु।

प्रजापत समाज कर्नाटक का चुनाव संपन्न, काँटनपेट मंदिर की जिम्मेदारी नई कार्यकारिणी को सौंपी

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com बेंगलुरु,13 अक्टूबर 2026। श्री प्रजापत समाज समस्त कर्नाटक ट्रस्ट, बेंगलुरु के काँटनपेट स्थित श्री यादे माताजी मंदिर परिसर में सोमवार, 12 अक्टूबर 2026 को समाज की आमसभा आयोजित की गई। इसमें कर्नाटक की 13 संस्थाओं के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में श्री कर्नाटक समाज काँटनपेट की नई कार्यकारिणी का चुनाव सर्वसम्मति से संपन्न हुआ। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को मंदिर की व्यवस्थाओं को सुचारु रूप से संचालित करने और समाज की गतिविधियों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। सर्वसम्मति से चुनी गई नई कार्यकारिणी आमसभा में सर्वप्रथम भूराम खरेडिया, आनेकल को समर्पात नियुक्त किया गया। उनकी अध्यक्षता में चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई। इसमें समाज के विभिन्न पदों के लिए पदाधिकारियों और सदस्यों का चयन सर्वसम्मति से किया गया। नई कार्यकारिणी मेंप्रधान पद की जिम्मेदारी नरसीदा बेरा को सौंपी गई। अणदाराम रांवरिया और भोराराम कवाड़िया उपप्रधान चुने गए। कुनाराम साडीवाल को अध्यक्ष तथा कुंदनमल जाजपुरा



उपाध्यक्ष कुंदनमल जाजपुरा, उपाध्यक्ष भंवरलाल कालबाल, कोषाध्यक्ष भरत कुमार पडीहार, उपकोषाध्यक्ष भगवान लाल कपूरपुरा, सचिव प्रकाश चन्द साडीवाल, उपसचिव नवरत्नमल कालबाल, उपसचिव जयराम भड़कोलिया, सूचना मंत्री मादुराम गाडुणिया, उप सूचना मंत्री हरीश राम जाजपुरा, उप सूचना मंत्री पारसमल हाटवा, व्यवस्था मंत्री रमेश कुमार कालबाल, उपव्यवस्था मंत्री मदनलाल हाटवा सलाहकार सदस्यों को भी मिली जिम्मेदारी समाज की गतिविधियों के संचालन और मार्गदर्शन के लिए

मदनलाल कपूरपुरा, भूराम खरेडिया, नाथूराम बाबरिया, जीवाराम घोड़ला और मदनलाल बेरा को सलाहकार सदस्य चुना गया। आमसभा में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों से अपेक्षा जताई गई कि वे समाज के सदस्यों के सहयोग से काँटनपेट स्थित श्री यादे माताजी मंदिर की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाएंगे। साथ ही मंदिर की गतिविधियों को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने और विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रयास करेंगे। समाज की एकजुटता और विकास पर

जोर कर्नाटक की 13 संस्थाओं के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में संपन्न चुनाव को समाज की संगठनात्मक गतिविधियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नई कार्यकारिणी के सामने मंदिर की व्यवस्थाओं को सुचारु बनाए रखने, समाज के सदस्यों के बीच समन्वय बढ़ाने और सामूहिक सहयोग से विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी होगी। समाज की ओर से नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को दायित्व सौंपे जाने के साथ उनसे अपेक्षा की गई कि वे आपसी सहयोग और सहभागिता के माध्यम से संगठन तथा मंदिर की प्रगति के लिए कार्य करेंगे।



भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com बेंगलुरु, 13 अक्टूबर 2026। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में संगठन को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र की मौजूदगी में कोप्पल जिले के नेता शंभुलिंगनगौड़ा पाटिल हलगेरी के नेतृत्व में कई कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। यह कार्यक्रम बेंगलुरु स्थित भाजपा के

प्रदेश कार्यालय 'जगन्नाथ भवन' में आयोजित किया गया। इस अवसर पर विजयेंद्र ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और भाजपा की नीतियों में विश्वास जताते हुए लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि नए सदस्यों के शामिल होने से कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में पार्टी के संगठन को मजबूती मिलेगी। हालांकि, इस राजनीतिक घटनाक्रम का क्षेत्रीय स्तर पर कितना प्रभाव पड़ेगा, यह आगामी संगठनात्मक गतिविधियों और

कर्नाटक में कथित स्टिंग ऑपरेशन पर सियासी घमासान, जांच के लिए दस्तावेज देने को तैयार डी.के. शिवकुमार

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com बेंगलुरु, 13 अक्टूबर 2026। कर्नाटक की राजनीति में कथित स्टिंग ऑपरेशन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। मुख्यमंत्री डी.के.

ने मामले की निष्पक्ष जांच कराकर कथित घटनाक्रम की सच्चाई सामने लाने की मांग उठाई है। मंत्रियों को सतर्क रहने की सलाह से शुरु हुआ विवाद डी.के. शिवकुमार ने 8 अक्टूबर को अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों

कांग्रेस विधायक रविकुमार गनिगा ने भी मामले से संबंधित सबूत होने का दावा किया। उन्होंने कथित घटनाक्रम में एक केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की भूमिका को लेकर आरोप लगाए। हालांकि,

इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित पक्षों की भूमिका की निर्धारण जांच के बाद ही किया जा सकता है। कुमारस्वामी ने पूछा, अब तक जांच क्यों नहीं? केंद्रीय मंत्री और जनता दल (सेक्युलर) के नेता एच.डी. कुमारस्वामी ने इस मामले को लेकर राज्य सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि यदि कथित स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, तो अब तक इसकी जांच क्यों नहीं कराई गई। कुमारस्वामी ने मामले की विस्तृत जांच कर कथित रूप से शामिल लोगों की पहचान करने की आवश्यकता पर जोर दिया। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी कहा कि यह पता लगाना महत्वपूर्ण है कि कथित स्टिंग ऑपरेशन के पीछे कौन है। इस घटनाक्रम ने राज्य की राजनीति में पारदर्शिता, जवाबदेही और जांच की निष्पक्षता को लेकर बहस तेज कर दी है। हालांकि, राजनीतिक नेताओं के बयानों

को जांच से प्रमाणित तथ्यों से अलग करके देखना आवश्यक है। निष्पक्ष जांच से ही सामने आएगी सच्चाई। कथित स्टिंग ऑपरेशन से जुड़े विवाद में फिलहाल कई सवाल अनुत्तरित हैं। इसकी वास्तविक प्रकृति क्या थी, क्या किसी को राजनीतिक रूप से फंसाने का प्रयास किया गया और इस घटनाक्रम में किन लोगों की भूमिका रही इन सवालों का उत्तर उपलब्ध दस्तावेजों, साक्ष्यों और संबंधित पक्षों के बयानों की जांच से ही मिल सकता है। यदि औपचारिक जांच शुरु होती है, तो उसकी निष्पक्षता और पारदर्शिता महत्वपूर्ण होगी। साथ ही, आरोपों से जुड़े सभी पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलना चाहिए, ताकि किसी निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले तथ्यों का समुचित परीक्षण हो सके। कांग्रेस और विपक्ष के बीच बढ़ सकता है टकराव कर्नाटक में यह विवाद सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी दलों के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ा सकता है। यदि जांच में नए तथ्य सामने आते हैं, तो उनका प्रभाव राज्य की राजनीतिक बहस और संबंधित नेताओं की भूमिका को लेकर होने वाली चर्चाओं पर पड़ सकता है। फिलहाल, इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कथित स्टिंग ऑपरेशन की वास्तविकता और उससे जुड़े आरोपों की सत्यता है। दस्तावेजों और प्रमाणों के आधार पर निष्पक्ष जांच ही राजनीतिक दावों तथा वास्तविक तथ्यों के बीच अंतर स्पष्ट कर सकती है।

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com बेंगलुरु, 13 अक्टूबर 2026। बेंगलुरु में आयोजित ओडू एक्स एनएमआईटी हैकार्थॉन 2026 में विद्यार्थियों की टीम ने 'स्काईलाइन'

प्रक्रियाओं को एक ही मंच पर संचालित करने में मदद करता है। परियोजना के पीछे की समस्या छात्र संगठनों में प्रचलित पारंपरिक कार्यप्रणाली से जुड़ी थी। सदस्य पंजीकरण के लिए स्प्रेडशीट, टिकट

चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए 'स्काईलाइन' प्लेटफॉर्म विकसित किया। इसमें सदस्यता और नवीनीकरण, प्रतीक्षा सूची के साथ टिकट प्रबंधन, मर्चेंडाइज के स्टॉक का हिसाब, खर्चों की मंजूरी तथा कार्यक्रमों में भागीदारी के लिए अंक आधारित पुरस्कार प्रणाली जैसी सुविधाएं शामिल की गई हैं। इसका उद्देश्य क्लब की विभिन्न गतिविधियों को एकीकृत करके प्रबंधन संबंधी कामकाज को अधिक प्रभावी बनाना है। इस परियोजना को तैयार करने के लिए रिफ़्ट और टाइपस्क्रिप्ट का उपयोग फ्रंटएंड विकास में, जबकि नोड.जेएस और एक्सप्रेस का इस्तेमाल बैकएंड के लिए किया गया। क्लाउड आधारित सेवाओं के लिए एडब्ल्यूएस तथा सॉफ्टवेयर के विकास और तैनाती की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए गिटहब एक्शंस सीआई /सीडी का उपयोग किया गया। टीम के अनुसार, हैकार्थॉन के दौरान केवल नए फीचर विकसित करना ही चुनौती नहीं था, बल्कि सॉफ्टवेयर की संरचना को व्यवस्थित बनाए रखना भी जरूरी था। विकास के बीच में कुछबड़े जटिल होने लगा, जिससे उसे समझना और आगे काम करना कठिन हो गया। ऐसे में टीम ने कुछ समय के लिए नए

फीचर जोड़ने का काम रोककर कोड की संरचना को साफ और व्यवस्थित करने का निर्णय लिया। टीम का मानना था कि इससे आगे का विकास अधिक सुचारु हो सकेगा। इसके साथ ही, टीम को यह भी तय करना पड़ा कि परियोजना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित स्वचालन का कितना उपयोग किया जाए। हैकार्थॉन में उपलब्ध समय, लागत और भविष्य में प्लेटफॉर्म को बड़े स्तर पर उपयोग करने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में निर्णय लिया गया। टीम के मुताबिक, इन फैसलों में समय लगा, लेकिन इससे उत्पाद की गुणवत्ता बेहतर बनाने में मदद मिली। इस उपलब्धि का श्रेय टीम के सदस्यों पार्थ खंडेलवाल, प्रतुष मिश्रा और सिद्धांत सोनी सहित पूरी टीम के सामूहिक प्रयासों को दिया गया। टीम ने ओडू, निट्टे मीनाक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एनएमआईटी), डेटाविज एनएमआईटी और आयोजन को सफल बनाने वाले स्वयंसेवकों के प्रति आभार व्यक्त किया। यह परियोजना छात्र संगठनों के प्रबंधन में डिजिटल तकनीक के उपयोग की संभावनाओं को सामने रखती है। हालांकि, ऐसे प्लेटफॉर्म की वास्तविक उपयोगिता उसके नियमित इस्तेमाल, आंकड़ों की सुरक्षा, संचालन लागत और उपयोगकर्ताओं की जरूरतों के अनुरूप आगे होने वाले सुधारों पर निर्भर करेगी।



शिवकुमार ने कहा है कि मामले की जांच होने पर वह इससे संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं। इस बीच सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी नेताओं के बीच आरोप–प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। विपक्ष

को कथित स्टिंग ऑपरेशन के जरिए फंसाने की कोशिशों को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी थी। उन्होंने दावा किया था कि उनके पास इस मामले से जुड़ी जानकारी और दस्तावेज मौजूद हैं। इसके बाद

